

ISSN 0975-4083

# रिसर्च जर्नल ऑफ आर्ट्स मैनेजमेन्ट एंड सोशल साइंसेस

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 2138 Impact Factor 4.875 (IIFS)  
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory  
ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक - 22, हिन्दी संस्करण, वर्ष-11, अक्टूबर-मार्च 2022

2022

[www.researchjournal.in](http://www.researchjournal.in)



आई. एस. एन. 0975-4083

# रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेस

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 2138

Impact Factor 4.875

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest,  
U.S.A. Title Id : 715204

अंक-22

हिन्दी संस्करण

वर्ष-11

अक्टूबर -मार्च 2022

प्रोफेसर ब्रजगोपाल

प्रधान सम्पादक

सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा

प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित

profbrajgopal@gmail.com

डॉ. अखिलेश शुक्ल

ऑनरेरी सम्पादक

प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित

akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल

अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा

सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा

rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

की मुख्य शोध पत्रिका



- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साइज के कागज में चारोंतरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेपित नहीं किया गया है।

### सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

- [researchjournal97@gmail.com](mailto:researchjournal97@gmail.com),
- [researchjournal.journal@gmail.com](mailto:researchjournal.journal@gmail.com)
- शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

### © सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00	-सदस्यता शुल्क -	
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय, नगद जमा की स्थिति में 75 रु. अतिरिक्त बैंक चार्ज जोड़ा जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स  
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट  
नागपुर

### संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कालोनी

रीवा- 486001 (म.प्र.)

E-mail- [researchjournal97@gmail.com](mailto:researchjournal97@gmail.com), [researchjournal.journal@gmail.com](mailto:researchjournal.journal@gmail.com)

[www.researchjournal.in](http://www.researchjournal.in)

दूरभाष - 7974781746

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनररी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

## अनुक्रमणिका

01.	महिला पुलिस की पारिवारिक एवं सामाजिक प्रिस्थिति (रीवा संभाग के विशेष संदर्भ में समाजशास्त्रीय अध्ययन) <b>अखिलेश शुक्ल, प्रियंका तिवारी</b>	09
02	भारतीय ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था का महत्व: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन <b>मीरा कुमारी</b>	20
03	शिक्षित एवं अशिक्षित कामकाजी महिलाओं के आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में) <b>शशांक पाण्डेय, प्रीतम सिंह, किरण पटेल</b>	26
04	कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुये युवकों कि मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में) <b>शालिनी शर्मा, सुनीत कुमार द्विवेदी, आशीष सिंह पटेल</b>	34
05	कोविड-19 के दौरान कामकाजी महिलाओं पर घरेलू हिंसा का प्रभाव (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में) <b>रुचि सिंह</b>	41
06	स्वास्थ्य पर राज्य के सार्वजनिक व्यय के प्रभाव का अध्ययन <b>मेधा डड्सेना, ए. के. पाण्डेय</b>	48
07	किन्नरों की सामाजिक स्थिति: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण <b>अंजू शुक्ला</b>	53
08	महिला अपराधिता "प्रकृति और पुनर्वास"	58
09	<b>गजानन मिश्र</b> भ्रष्टाचार (भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक विश्लेषण)	67
10	<b>रश्मि दुबे</b> भ्रष्टाचार एवं कालाधन: एक वैश्विक समस्या का अध्ययन <b>अनिल द्विवेदी</b>	74
11	विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास <b>रवेन्द्र राजपूत</b>	85
12	आर्टिकल 370 और कश्मीर समस्या <b>अर्चना दीक्षित</b>	101
13	कृषि वित्तीयकरण तथा रूपांतरण (सीधी जिले के विशेष संदर्भ में (1991 से 2010 तक)) <b>सौरभी गुप्ता</b>	109
14	स्वतंत्रता-संग्राम में दलित नायकों का योगदान: एक समीक्षात्मक अध्ययन <b>आशीष कुमार</b>	122
15	महात्मा गांधी का समाज के उत्थान में भूमिका <b>सिद्धार्थ मिश्र</b>	129
16	अकबर की सेना में राजपूत सैन्य अधिकारियों का योगदान <b>मीनाक्षी सिंह कर्चुली</b>	133
17	अकबर एवं जहांगीर कालीन धार्मिक नीति: उत्तर भारतीय समाज के विशेष संदर्भ में <b>प्रियंका भारती</b>	138
18	मैहर तहसील का पुरातत्व <b>धीरजलाल विश्वकर्मा</b>	148

19	मनरेगा में महिलाओं के समावेशी विकास का अध्ययन मिर्जा शहाब शाह, सद्दाम खान, रामलखन सिंह	151
20	छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक व्यय का शिक्षा पर उसके प्रभाव का अध्ययन मेघा डिसेना, ए. के. पाण्डेय	157
21	छत्तीसगढ़ राज्य के योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण शशिकिरण कुजूर	162
22	भारत की राजकीय नीति की प्रवृत्तियाँ: वर्तमान सन्दर्भ में कुमुद श्रीवास्तव	168
23	कृषि विपणन की दशा का समीक्षात्मक मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष सन्दर्भ में)	175
24	पुरुषोत्तम प्रसाद बाल्मीकि, भानु साहू जनपद प्रतापगढ़ के औद्योगिक विकास में आंवला (एक भौगोलिक अध्ययन) इंदु मिश्रा	182
25	भारतीय लोक कला के विविध आयाम उपासना राज	187
26	भारतीय परम्पराओं में बसी विभिन्न प्रकार की लोक कलाएँ निशा गुप्ता	194
27	दिव्यांग तथा संगीत का परस्पर संबंध निशा पाठक	200
28	महाकवि कालिदास की कृतियों में संगीत निष्ठा शर्मा	205
29	संगीत में विद्युतीय उपकरणों की भूमिका खूशब	212
30	कोविड-19 के ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा- चुनौतियाँ स्मिता मसीह	217
31	उच्च शिक्षा में परिवर्तन एवं अवलोकन प्रत्यूष बत्सला द्विवेदी	225
32	मुगल काल में राजपूतों की सामाजिक स्थिति मीनाक्षी सिंह कर्चुली, एस.एस. चौहान	230
33	उत्तर प्रदेश में प्रार्थमिक शिक्षा की स्थिति एवं विकास निशा गठौर, जितेन्द्र सिंह	236
34	राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 की शैक्षिक जगत को देन रवेन्द्र राजपूत	242
35	प्रवासी साहित्यिक परिदृश्य में उषा प्रियंवदा का साहित्य अमित शुक्ल	255
36	हिन्दी मीडिया सामाजिक उपादेयता संकट और संभावनाएँ सूरजमुखी	262
37	रामभक्ति व विधायक भावनाओं का आकर ग्रन्थ-रामचरित मानस सुनीता द्विवेदी	270
38	'गा' पद की अर्थ मीमांसा ज्योत्स्ना द्विवेदी	276
39	मृच्छकटिक कालीन सामाजिक प्रथा एवं कुरीतियाँ लक्ष्मीकान्त मिश्र, कमलेश कुमार थापक, आदित्य तिवारी	280

## भ्रष्टाचार (भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक विश्लेषण)

• रश्मि दुबे

**सारांश-** भ्रष्टाचार भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में इस सीमा तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि कदम-कदम पर लोकतन्त्र के सिद्धान्तों एवं आदर्शों की अवहेलना की जाती है। सिद्धान्त के रूप में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रजातन्त्र की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखेंगे। संसद से यह आशा की जाती है कि वह कार्यपालिका को अनियन्त्रित होने से रोकेगी, न्यायपालिका से राज्य की सत्ता से आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आशा की जाती है और संचार माध्यमों से सार्वजनिक जीवन में घूसखोरी तथा अन्याय को रेखांकित करने की अपेक्षा की जाती है। यदि भारतीय प्रजातन्त्र के अस्तित्व को बनाए रखना है तो आवश्यक है कि ये कार्य पूरे किए जाए।

**मुख्य शब्द-** भ्रष्टाचार, राजनीति, भारतीय दंड संहिता

**परिचय-** भ्रष्टाचार से आशय है-भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्ट-व्यवहार। यह सर्वविदित है कि समाज और शासन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होने के लिए सार्वजनिक हित में व्यवहार के कुछ आदर्श प्रतिमान सुस्थापित हैं। उसमें नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, पद एवं सत्ता का सदुपयोग मुख्य रूप से सन्निहित किए जा सकते हैं। ये प्रतिमान स्वस्थ समाज की परम्पराओं पर आधारित हैं। समाज रूपी व्यवस्था की सुदृढ़ता इन पर ही निर्भर है। अतएव प्रत्येक समाज इनका पक्षधर है। ये प्रतिमान ही नैतिक आदर्शों के प्रतिरूप माने जाते हैं। इनका पालन ही नैतिक आचार अथवा सदाचार है तथा उल्लंघन भ्रष्टाचार है। आशय यह है कि उपरोक्त मान्य एवं सुस्थापित नैतिक आदर्शों के विपरीत किए जाने वाले व्यवहार भ्रष्टाचार के द्योतक हैं। अनैतिकता, असहिष्णुता, कर्तव्यउपेक्षा एवं निजी हित के लिए पद एवं सत्ता का दुरुपयोग आदि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कन्साईज आक्सफोर्ड शब्दकोश में भ्रष्टाचार का अर्थ है, “रिश्वत अथवा अवैधानिक और अनुपयुक्त साधनों से गलत या अनैतिक कार्य की ओर उन्मुख होना तथा सही और नैतिक कार्यों से विरत् होना भ्रष्टाचार है।”

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर, उत्कृष्टता महाविद्यालय  
सागर (म.प्र.)

उपरोक्त उद्दण्ड के आलोक में, जहाँ प्रस्ताचार को अनैतिकता से जोड़ा गया है, यह कहना ज्यादा सार्थक है कि वास्तव में अनैतिकता प्रस्ताचार का पर्याय बन चुकी है। इसलिए प्रस्ताचार को सही अर्थों में समझने के लिए नैतिकता को समझना अनिवार्य प्रतीत होता है। नैतिकता का शाब्दिक अर्थ वैचारिक निर्धारण और अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए अधिकारों का उचित उपयोग है। नैतिकता पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वक्तव्य है कि “जिस काम को करने के बाद आप सुखद अनुभव करें वह नैतिक और जिसे करने के बाद आप बुरा महसूस करते हैं, वह अनैतिक है”:

हेमिंग्वे का ‘मुख’ सम्बन्धी कथन भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक सुख को प्रतिष्ठित करता है। यह आत्मिक सुख स्वहित नहीं बल्कि पर-हित एवं सार्वजनिक हित सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता है कि वह व्यवहार जो सार्वजनिक हित में हो, स्वहित का पोषक न हो तथा सुस्थापित मान्यताओं के अनुकूल हो, सदाचार के रूप में जाना जाएगा। लेकिन ऐसा व्यवहार जो स्वहित का पोषक हो, सार्वजनिक हित का किरणी हो, लोगों को कष्ट देने वाला हो एवं सुस्थापित मान्यताओं का उल्लंघन करता हो, प्रस्ताचार की श्रेणी में जाएगा। नैतिक आदर्शों की उपेक्षा एवं सदाचार का अभाव, प्रस्ताचार संरक्षण (जो साम्प्रदायिकतावाद, जातिवाद, भाई-भतीजावाद एवं पक्षपात पर आधारित होता है) एवं अनुचित प्रभाव की रूपों में अभिव्यक्त होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सम्पूर्णनन्द ने कहा है कि “प्रशासकीय कार्य के सम्पादन में एक के द्वारा दूसरे को धन देना ही सच्चरित्रता के अभाव को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र रूप नहीं है। यह अनेक रूप धारण कर सकता है, जो किसी भी प्रकार कम निन्दनीय नहीं होता। उदाहरण के लिए संरक्षण द्वारा एक व्यापक क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है, जो दायित्वों एवं त्रुटियों की दृष्टि से धातक बुराई का घोटा सिद्ध हो सकता है। जिसे हम बुरा समझते हैं उसके प्रति आंखें मूँद लेना, अपराधी को अनैतिक कार्यों की छूट देना और अपने दुष्कृत्यों के लिए उसे अपने दण्ड से बचने देना, पद शृंखला में किसी उच्च पदविधिकारी के स्थान पर, जो वास्तव में दोषी है, उसके किसी अधिनस्त को बलि का बकरा बनाना, गलत सूचना देना या किसी महत्वपूर्ण सूचना या तथ्यों को प्रस्तुत न करके उन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप में दबाना और तथ्यों को जानबूझ कर गलत निर्णय हेतु प्रस्तुत करना।”<sup>1</sup>

राजनीतिक चिन्तन में, राजनीतिक प्रस्ताचार के सन्दर्भ में, आज जो सामान्य-सी अवधारणा विकसित हुई है उसके अन्तर्गत यह माना जाने लगा है कि स्वहित की येन-केन-प्रकारे धूर्ति की भावना राजनीतिक कार्यों का आधारभूत प्रेरणास्रोत है। मैकियावेली के दर्शन में ‘हित-पोषण’ का यह दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्वार्थ संदर्भित चिन्तन का एक पक्ष हाँस के राजनीतिक दर्शन में भी देखने को मिलता है। लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि हाँस जहाँ जन सामान्य के हित पर बल देते हुए उसकी धूर्ति के लिए लेखियाथन जैसे निरंकुश शासक की बात करता है, वहीं मैकियावेली प्रिंस (शासक) के स्वहित पर बल देता है।<sup>2</sup> जहाँ तक प्रस्ताचार की बात है, सामान्यतः, व्यवहार में इसे निजी आर्थिक हित हेतु सरकारी

पद के दुरुपयोग के रूप में देखा जाता है। पद का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने को ही प्रस्ताचार माना जाता है, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट दियाउंदेता है तथा उसमें आम आदमी का जीवन शीघ्र प्रभावित होता है। इस तरह वह मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, जो अपनी सरकारी स्थिति का लाभ उठा कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित आर्थिकार्जन करता है।<sup>3</sup> प्रस्ताचार की एक सामान्य-सी परिमापा इस प्रकार दी जा सकती है, कि किसी सार्वजनिक पद पर अमीन किसी व्यक्ति (राजनीता अथवा सरकारी अधिकारी) द्वारा अपने निजी आर्थिक हितों को पूर्ति के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना प्रस्ताचार कहा जाता है।

राजनीति को विकृत करने में धन तथा भौतिक संसाधनों की तरह नारी सौन्दर्य का प्रयोग के अनेक उदाहरण भी समय-समय पर संज्ञान में आते रहे हैं। इस ताह के अनेक प्रकरणों में यह देखा गया कि सत्ता प्राप्ति की अन्यै दौड़ में मकलता पाने हेतु अनेक राजनीतिक व्यक्तियों ने नारी सौन्दर्य का उपयोग करते हुए अपने राजनीतिक प्रभाव को सफलतापूर्वक बढ़ाया। भारत में राजनीति और राजनेताओं के चित्र में निर्वट अब आतंक और हिंसा के स्तर तक पहुँच चुकी है। भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और टी. एन. शेपन का कहना है कि, “राजनेता अब मात्र लूट से ही सन्तुष्ट नहीं होते बल्कि वे पुराने विदेशी आक्रमणकारियों की उस शैली में व्यवहार करते हैं कि यहाँ के बदल को लटो और उसके बीची-बच्चों को दास बना लो।” सत्ता के लिए होने वाले निवार्दनों में अनैतिक साधन अपनाकर चुनाव लड़ना अब आम बात हो गई है। अब तो इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिल चुके हैं कि राजनीतियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए चुनाव में सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग किया जाता है। चुनावों में दूर्घट वादे करके बोट प्राप्त करना, जनता के बीच थोंती, साझी, कम्बल तथा शराब वितरित करवा कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना तथा साथ ही साथ लोगों में पैसे बांट कर बोट खरीदना गम्भीर प्रस्ताचार है। यद्यपि राजनेता इसे राजनीति का एक अंग मानते हुए इसे ‘राजनीतिक चातुर्थी’ कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रस्ताचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं क्योंकि यह सारा खेल राजनेताओं द्वारा अपने पद सम्बन्धी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए निजी हित के लिए खेला जाता है।

भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-9 में प्रस्ताचार को विस्तृत रूप में परिशिरित किया गया है। इसमें उपबन्धित धारा 16। प्रमुखतः लोक सेवकों में प्रस्ताचार से सम्बन्धित है जिनकी परिधि में घूस अथवा रिश्वत और सहवर्ती अपराध, विधि निरुद्ध कार्य एवं लोक सेवकों के प्रतिरूपण सम्बन्धी कार्य आते हैं। धारा 16। में उपबन्धित है कि वह व्यक्ति प्रस्ताचार का दोषी माना जाएगा जो, आज किसी अवैध कार्य को करने के लिए या वैध कार्य को अवैध तरीके से करने के लिए या अपराध को दबाने अथवा छिपाने के लिए प्रायः लोक सेवकों को घूस अथवा रिश्वत दी जाती है। यदि कह दिया जाए तो जिसमें सभी प्रकार के अवैधतिक सम्पादन एवं अभिलाषाएं सम्मिलित हैं और वैध जिसमें सभी प्रकार के अवैधतिक सम्पादन एवं अभिलाषाएं सम्मिलित हैं और वैध परिश्रमिक से भिन्न किसी भी प्रकार का परितोषण इसके अन्तर्गत आता है। भारतीय

दण्ड संहिता के 161 से 165 एकी धारों को समाप्त करके उसके स्थान पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 को प्रदर्शन में ला दिया गया है लेकिन भ्रष्टाचार के संबंध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दी गई परिभाषा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में भी उसी रूप में शामिल किया गया है।<sup>1</sup>

**वस्तुतः** भ्रष्टाचार भारतीय लोकतात्रिक व्यवस्था में इस सीमा तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि कहम-कहम पर लोकतन्त्र के सिद्धान्तों परं आदर्शों की अवहेलना की जाती है। सिद्धान्त के रूप में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रजातन्त्र की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखेंगे। संसद से यह आशा की जाती है कि वह कार्यपालिका को अनिवार्तित होने से रोकेगी, न्यायपालिका से राज्य की सत्ता से आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आशा की जाती है और संचार माध्यमों से सार्वजनिक जीवन में घृसखोरी तथा अन्याय को रोकांकित करने की अपेक्षा की जाती है। यदि भारतीय प्रजातन्त्र के अस्तित्व को बनाए रखना है तो आवश्यक है कि ये कार्य पूरे किए जाए।<sup>10</sup>

धन आज राजनेताओं के जीवन में प्रभावी भूमिका अदा करने लगा है। विशेषतः चुनावों के पूर्व, उनके मध्य एवं तत्पश्चात् विशेष रूप से सरकारों के बनाने और उन्हें अपदस्थ करने में राजनेता का प्रभाव आज इस तुला पर आंका जाने लगा है कि वह अपने दल के लिए कितना धन एकत्र कर सकता है। धन हमारी राजनीतिक व्यवस्था में आज सभी दुर्दुणों का द्वात बन गया है। यह वह माध्यम है जो पूरे राजनीतिक तन्त्र को गम्भीरता से प्रभावित एवं विकृत कर रहा है। राजनीतिक तन्त्र में काले धन की सबसे बड़ी आपूर्ति बढ़े और मध्यम वर्ग के व्यापारिक धरानों द्वारा जाती है जो सभी दलों को पैसा देते हैं, क्योंकि यथा-स्थिति बनाए रखने में उनका हित है। उद्योग क्षेत्र ने राजनीतिक तन्त्र को भी सभी चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को और अनेक स्थानीय दलों को पैसा देकर अपने गिरफ्त में ले लिया है। लाइसेंस-कोटा परिवर्त राज और प्रत्येक दल के नेताओं द्वारा पैदा किए गए पैसे का परिणाम यह हुआ कि चुनावों में भारी पैसा लगाया जाने लगा। राजनीति में भ्रष्टाचार का पर्याय बने अनीतिक माध्यमों से एवं साधनों से अवैध धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति ने अब संस्थान रूप धारण कर लिया है। उन्हें समान भी प्राप्त हो रहा है। लूट और अपराध, जो निम्न स्तर पर आरम्भ हुए थे, वे अब नई दिल्ली, मुम्बई और अन्य प्रमुख राज्यों की राजधानियों में उच्च स्तर पर बढ़कर विशालकाय राक्षस की तरह हो गए हैं। भारत वर्ष में भाई-भतीजावाद के पक्षपापण करने वालों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जब तक पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सदस्य को, जोकि सुविधाविहीन है, उसके किसी सम्बन्धी अथवा उसी जाति के अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा सहयोग नहीं प्रदान किया जाएगा तब तक वे अपने से ज्यादा सुविधा एवं साधन सम्पन्न प्रतियोगियों के रहते कोई अच्छा पद कीसे प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय राजनीति में तो इस धारणा ने एक आम समर्थन और वैधानिक स्थिति भी प्राप्त कर ली है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सरकारी नियुक्तियों में मंत्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने संग-सम्बन्धियों अथवा जाति के लोगों की नियुक्तियों को वरीयता दी जाती है, लेकिन कभी भी उनका यह आचरण गम्भीर बहस का मुद्दा नहीं बन पाता और न ही जनमानस में

उत्तेजना का संचार करता है। सामान्य जनता इसके प्रति उदासीन-सी लगती है; और अब तो आम लोगों ने भी सम्प्रदाय तथा रक्त-सम्बन्धों को मुनाफा प्राप्त कर दिया है।<sup>11</sup>

वर्तमान भारत के लिए भ्रष्टाचार से अधिक प्रामाणीक अन्य विषय की कल्पना शायद ही की जा सके। समाज के हर स्तर और क्षेत्र को भ्रष्टाचार प्रभावित कर रहा है। राजनीति-प्रशासन के गठजोड़ में तीव्र से व्याप्त हो गए भ्रष्टाचार ने, जिसने धन और प्रतिष्ठा के पर्याय के रूप में स्थान ग्रहण कर लिया, विगत कुछ दशकों से समाज के हर वर्ग में अपनी जड़ों को मज़बूती से जमा लिया।<sup>12</sup> भ्रष्टाचार के बारे में एडवर्ड मिच्चन का मत है कि, भ्रष्टाचार संवैथानिक स्वतन्त्रता का लक्षण है।<sup>13</sup> यह कहना कठिन है कि मानव इतिहासकार मिच्चन का यह वक्तव्य अंग्रेजीतमक है या विश्वेषणात्मक। जो भी हो भ्रष्टाचार के लिए अधिकतम संवैथानिक स्वतन्त्रता न तो किसी देश में उत्पन्न है और न ही इसका बहुत आशा की जा सकती है।

भारत में भ्रष्टाचार को एक नया आयाम दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त हुआ। इस योजना में भारी पैमाने पर सांवैज्ञानिक धन के व्यवहार या जिसने भारतीय इतिहास में पहली बार गतिनीति, उद्योगपति और नौकरशाह को एक-दूसरे के निकट ला खड़ा किया क्योंकि इसके अन्तर्गत गांधीजी आप में समुचित वृद्धि और उद्योग-धन्यों पर विशेष बल आदि बातों को लक्ष्य बनाकर कार्य प्राप्त किया गया।

सरकार ने भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में कुछ गम्भीरता दिखाई। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1947 को अधिनियमित किया गया और उन्हीं वर्षों में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डी.एस.पी.ई.) की स्थापना की गई। यह भ्रष्टाचार विरोधी संगठन बाद में 1963 में स्थापित के द्वारा यांच बूरो का आंग बन गया। सरकारी अधिकारियों को ईमानदार बनाए रखने के लिए कई और कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय किए गए। इन उपायों में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में यह परिवर्तन शामिल है कि, “अपनी जाति वैध आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति रखने के लिए अरोपित अधिकारी को ही अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा।”<sup>14</sup> दुर्भाग्य से इन वैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद भ्रष्टाचार काफी तेजी से बढ़ा और यह उस स्तर पर पहुंच गया जिसका संघाननम कर्मटी ने उन वर्षों में नहीं की थी। भारत में सामान्यतः यह देखा जाता है कि स्वतंत्र व्यवस्था के अनुपात से अधिक सम्पत्ति रखने के लिये दबाव डालती है। “मानव नियम कानून भ्रष्टाचार अधिकारियों पर भ्रष्ट होने के लिये दबाव डालती है।” भारत में नियम कानून भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं लेकिन यह भी कहा जाता है कि कानून समत वाक्य करने वाले को रोकना चाहते हैं लेकिन यह भी कहा जाता है कि कानून भारी-भरकम, भायक और कर्मचारी प्रशासन को अपांग बना देते हैं। कई कानून भारी-भरकम, भायक और कर्मचारी अव्यावहारिक है। मुख्य बात यह है कि नियमों को प्रत्येक घटना पर सजग होना चाहिए अव्यावहारिक है। मुख्य बात यह है कि नियमों को प्रत्येक घटना पर सजग होना चाहिए लेकिन अक्सर कोई कमी निकाल ली जाती है। नए नियम कानून की अधिकता अधिकारियों को कोन्नो-मुख्य कर व्यवस्था को नकारा बना देती है। भारी भरकम कानूनों अधिकारियों को कोन्नो-मुख्य कर व्यवस्था अनिश्चित हो जाती है और विलम्ब को नजरअन्दाज कर के चलते प्रशासनिक प्रक्रिया अनिश्चित हो जाती है कि कानून भारी-भरकम, भायक और कर्मचारी प्रशासन को अपांग बना देते हैं। कई कानून भारी-भरकम, भायक और कर्मचारी अव्यावहारिक है। मुख्य बात यह है कि नियमों को प्रत्येक घटना पर सजग होना चाहिए अव्यावहारिक है। इसलिए वे अक्सर नियम कानूनों की परवाह नहीं करते। पाना असम्भव हो जाता है। इसलिए वे अक्सर नियम कानूनों की परवाह नहीं करते। उदाहरण के लिए, “चूंकि कोई भी ठेकेदार नुकसान में कार्य नहीं करना चाहता इसलिए

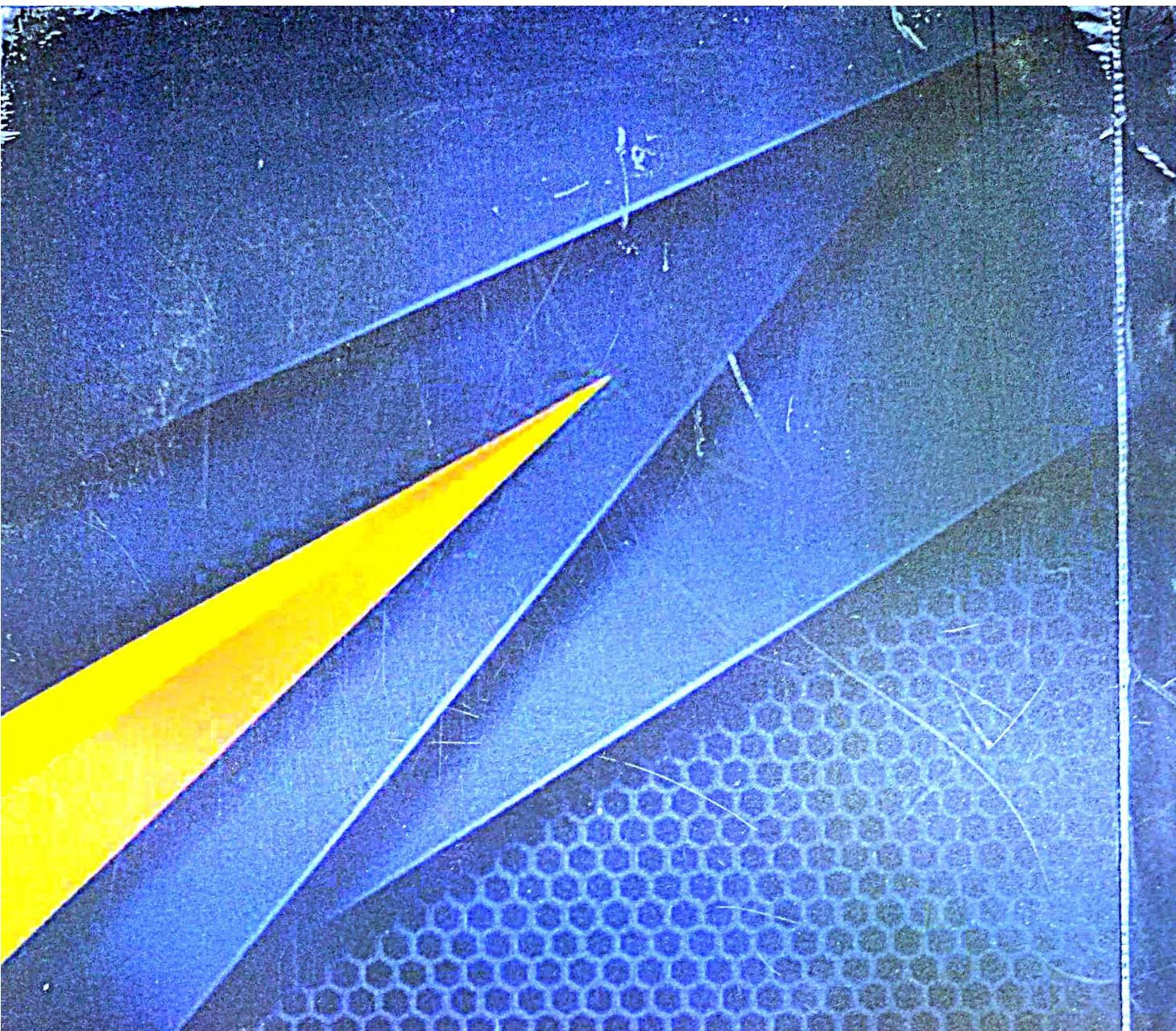
वह इंजीनियर को गत विकास देता है। जब बजरी निकाली जाती है तो उसे मिट्टी बता रेता है, जब मिट्टी खोदी जाती है तो उसे कटार मान लिया जाता है और यदि वह कटार होता है तो उसे पत्थर मान लिया जाता है। छीजन स्थिति को और भी उच्चार बना देता है तो केवर अनावश्यक नुकसान डरने को हीमार नहीं होता। राजनेता भी उनसे धन लेना चाहते हैं। अन्ततः इंजीनियर को गत विकास देना पड़ता है। यदि कोई ईमानदार ऐसा नहीं करता तो उसे डराया-धमकाया जाता है अथवा अल्पवाहिक नियम कानून और राजनीतिक हस्तक्षेप भ्रष्टाचार के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।

स्फूतन्त्रता प्राप्ति के बारे जो नियम, कानून जाहिर तौर पर जनता के हित के लिए थे, वे व्यक्ति के दीनिक व्यवहार में उन लोगों के हित मोपक बन गए जिनके हाथ में सत्ता थी और जिनके मित्र तिसें दार और करीबी थे। देश और जनता की सम्पत्ति को रोके अपनी सम्पत्ति के रूप में उपयोग करते हुए एक समानान्तर सत्ता चलाने लोगों उनकी कामगारी कानून सम्मत न होने और प्रतिक्रिया लगाने योग्य होने के बावजूद आज समाज में खूबी काढ़ रही है। यह निविराद है कि आज राजनेता, बड़े नौकरशाह और उनके करीबी विस्तोरात यथा मित्र सन्देह के घेरे में हैं।

आज भारत में भ्रष्टाचार एक सर्वव्यापी समस्या बन कर रह गया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अद्युता नहीं है। यह वर्तमान भारत में जीवन शैली बन चुका है। इसकी स्वीकारन्ता सामाजिक क्रियाकलापों में भी स्मार्ट रूप से परिलक्षित होती है और वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, परिसंस्करण में इसके समाधान के लक्षण दू-दूर तक अन्यकार का गर्भ में है, लेकिन इससे यह नियकर्ण नहीं निकाला जाना चाहिए कि समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। इस समय भारत में भ्रष्टाचार की समस्याविकट अवश्य है तथा जहां प्रट लोग कम होते हैं वहां यह व्यक्तिगत समस्या होती है और प्रटों से व्यक्तिगत स्तर पर निपटा जा सकता है किन्तु जहां प्रटाचार पौर समाज में फैला हो, जैसा कि आज हमारे देश में है, तो पूरी व्यवस्था में सुधार की अवश्यकता होती है। कुछ कोरिशा से ही देश को इस बुराई से मुक्त नहीं कराया जा सकता। इससे जूझने के लिए गढ़व्यापी सकल्प, व्यापक जन जागृति एवं आम जनता की सोच को बदलने की आवश्यकता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. कसाइज आक्सफोर्ड शब्दकोश, पृष्ठ 45
2. श्रीवास्तव, पी. बालेश्वरी, नीतिकाल, राजनीति और भारत, पालियम इंडिया, 1998
3. संपूर्णिंद, इन्टरप्रिट इन पाल्क, एडमिनिस्ट्रेशन, बुलेटिन आफ इन्स्टीट्यूट द पाल्क
4. ईमिनिस्ट्रेशन, प्रत्यान्तरीन सेटी, 1957
5. प्रतिका, प्रस्तुता, 16 आप्रूवा, 1994
6. बांबा, जी.एस., करप्तन पालियम कल इन ईडिया, पालत युक सार्विस, नई दिल्ली, से उद्धृत
7. रोपन टी.एस., भारत पतन कीओर, राजपाल एण्ड इन्स्टीट्यूट, 1995
8. अग्रवाल, बिहारीप्रसाद, भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार, राष्ट्रपद्धतिक्षेप, नई दिल्ली 2005



# **सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज** **रीवा- 486001**

**Registered under M.P. Society Registration Act, 1973  
Reg. No. 1802, Year 1997**

